Resumption of Production in Flooded Mines

*214. SHRI D. N. TIWARY: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the coal mines in Jharia, Dhanbad and Asansol which were flooded due to September, 1978 floods have been dewatered;

(b) whether the production in those coal fields has come to the pre-flood level;

(c) whether it is also a fact that the stocks at pitheads have considerably increased; and

(d) whether despatches have also increased and the demands of Railways and other industries are being met in full?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की सभी बाढ़ग्रस्त खानों और ईस्टर्न कोलफील्ड्स के पाँच खनन जिलों को छोड़कर बाकी सभी खानों से पानी निकाल दिया गया है। इन बचे हुए पांच जिलों से भी पानी निकालने का काम चल रहा है और इसी महीने मे सारा पानी निकाल दिया जायेगा।

(ख) उत्पादन तो जितना बाढ़ के पहले होता था अब उससे भी अधिक होने लगा है।

(ग) जी हां। अक्टूबर, 1978 से अब तक खान मुहानों पर 2 मिलियन टन से अधिक की वृद्धि हुई है।

(घ) कोयले का प्रेषण भी बढ़ गया है। वर्तमान उत्पादन और खान मुहाना स्टाक दोनों मिलाकर रेलों और अन्य उद्योगों की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है।

श्री द्वारिकानाथ तिवारी : अध्यक्ष जी, इसी हाउस में कई बार कहा गया है कि कोयले के अभाव में गाड़ियां नहीं चलती हैं, फैक्ट्रीज, बन्द हो जाती हैं, स्टील फैक्ट्रीज का काम भी ठप्प हो जाता है और आप के यहां 2 मिलियन से ज्यादा का स्टाक है, मैं जानना चाहता हूं कि उस कोयले को इन जगहों पर भेजने में क्या कठिनाई है ? रेलवे मिनिस्टर कहते हैं कि हम गाड़ियां दे रहे हैं, आप कहते हैं कि हमारे यहां पिट-हैड्स पर काफी कोयला जमा है, तब फिर ऐसी बात क्यों होती है कि फैक्ट्रीज बन्द हो जाती हैं, रेलें बन्द हो जाती हैं और काम ठप्प जाता है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, सवाल बाढ़ से कोयला खदानों के प्रभावित होने का था। बाढ़ से कोयला खदानें भी प्रभावित हुई थीं और रेलें भी प्रभावित हुई थीं और इसी वजह से, हालांकि खान मुहानों पर कोयला पड़ा हुआ है, फिर भी कई जगहों पर कोयला पहुंचाने में परेशानी हुई है, हालांकि सब जगहों पर कोयला पहुंचाया जा रहा है।

श्री द्वारिकानाथ तिवारी : कोयला सब जगह नहीं पहुंच रहा है। उद्योगों के अतिरिक्त जहां ईंटा पकाने का काम होता है, उन को भी बहुत कम कोयला मिल रहा है। बहुत-सा ईंटा बारिश की वजह से नष्ट हो गया है, क्योंकि कोयले के अभाव में वह ईंटा पक नहीं सका। जब कि आप कहते हैं कि सब जगह भेजा जा रहा है। इन दोनों में क्या तालमेल है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल प्रायोरिटी का है। राज्य सरकार जब कोयले की मांग स्पान्सर करती है तो रेलवे विभाग उस पर प्रायोरिटी तय करता है और ईंटा पकाने के लिये राज्य सरकार कितनी मांग स्पान्सर करती है, उसी हिसाब से रेल विभाग द्वारा प्रायोरिटी दी जाती है, कोयला विभाग बीच में कहीं नहीं आता है।

श्री राम सेवक हजारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं—कोयले का जो उत्पादन अभी है, उस की वितरण प्रणाली में गड़बड़ी होने के कारण लोगों को कोयला सुलभ नहीं हो पा रहा है। कोयले में गड़बड़ी यह है कि जहां कोयले का उत्पादन होता है, वहां ब्लैक में लोगों को कोयला दिया जाता है और वह कोयला बाजारों में अधिक कीमत पर बिकता है। इस प्रकार की शिकायतें कई बार की गई हैं और केन्द्रीय सरकार के सामने भी ये शिकायतें आई हैं। पिछले तीन-चार महीने पहले इस सम्बन्ध में जांच भी हुई थी, लेकिन अधिकारियों ने उस मामले को दबा दिया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं—क्या वे कोयले की वितरण प्रणाली में कोई ठोस सुधार लाने वाले हैं जिससे लोगों को सुलभ तरीके से कोयला मिल सके ?

श्री जनेश्वर मिश्र : पिट-हैड पर कोयला ब्लैक में बिल्कुल नहीं बिकता, मैं माननीय सदस्य को इस बारे में आश्वस्त करना चाहता हूं और कोयला अपने डिपोज पर बिना ब्लैक किये हुए जाता है। अगर वहां कहीं ब्लैक बिकता हो, तो दूसरी बात है लेकिन पिट-हैड्स पर नहीं बिकता है। ...(व्यवधान)...

श्री किशोरी लाल : माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि पिट-हैड्स पर जो कोयला है, उस को ये प्रायरटीज पर देते हैं। सारे सदन के माननीय सदस्यों को यह पता है कि हिन्दुस्तान भर में यह चर्चा है कि एक रैक या दो रैक को प्रायरटीज दे कर 1,000, 2000 रुपये ले लिये जाते हैं। क्या ये मंत्री जी या रेलवे मंत्री जी सदन

को यह बात बता सकते है कि कितने लोगो को प्रायरटीज दी गई है। पब्लिक सेक्टर सफर करता है और प्राइवेट सेक्टर वालो को प्रायरटीज दे कर कोयला बेच दिया जाता है। अभी आप ने यह देखा कि डेयू के अन्दर कोयला की दिक्कत है और केवल एक दिन का कोयला वहां पडा हुआ है जिसके कारण सब की जान निकली हुई है कि बिजली मिलेगी या नही मिलेगी। मै जानना चाहता हूं कि पिछले साल भर में एनर्जी मिनिस्टर साहब ने कितने लोगो को प्रायरटीज दी है।

MR. SPEAKER: The same question is repeated, repeated and repeated.

श्री किशोर लाल : रेलवे मत्री जी ने कितने रेक्स को जल्दी आने के लिए प्रारयरटी दी है, यह आप मेम्बरो को बता सकेंगे ?

श्री जनेश्वर मिश्र : यह हम लोगो का विषय नही है। मैंने पहले ही कहा है कि राज्य सरकारें जो माग स्पान्सर करती है, उन पर रेलवे मिनिस्ट्री प्रायरटी तय करती है। कोयले के विभाग से इस का सम्बन्ध नही है। गलत जगह पर माननीय सदस्य सवाल पूछ रहे हैं।

श्री हीर चाई : माननीय मत्री जी ने कहा है कि कोयला पिटहैड पर ब्लैक में नही बिकता है, यह बात ठीक है। उन्होंने यह भी कहा कि कोयले की कमी है लेकिन जब कोयले की कमी है तो उस रेट पर वह नही मिलना चाहिए, यह भी हम जानते हैं। अगर कोयले की कमी है तो फिर ब्लैक में कोयला कहा से मिलता है। इस का मतलब यह है कि खुलेआम ब्लैक हो रहा है और ब्लैक करने वालो को प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं मत्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि इस को रोकने के लिए वे क्या रुख अख्तियार कर रहे है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : मै फिर यह कहना चाहता हू कि एनर्जी मत्रालय का काम केवल कोयले का उत्पादन करना है। उत्पादन करने के बाद, पिटहैड्स पर कोयले का ब्लैक नही होता है, यह मैं कई बार बता चुका हूं।

Education in Sainik Schools

*215. SHRI DAYA RAM SHAKYA: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF DEFENCE be pleased to lay a statement showing:

(a) what amount of scholarship per year is being sanctioned by Government for a student in the Sainik Schools, Kapurthala, Kunjpura, Nagrota;

(b) how much out of this sanctioned amount is spent on the food and clothing of each student separately in a year; what happens to the remaining amount; whether the amount spent for clothing and food meets the required standard, if not, why;

(c) is it a fact that the standard of education in these schools is going down day by day in comparison to the standard at the time of the admission to these schools; and

(d) if so, what steps are being proposed or are being taken to raise it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (PROF. SHER SINGH): (a) to (d). A Statement is laid on the Table of the House

Statement

(a) The Governments of Punjab and Haryana grant scholarships at the rate of Rs. 3500 per boy per annum. The rate of scholarship sanctioned by the Government of J. & K. is Rs. 3000 per boy per annum. These State Governments also grant clothing allowance at the rate of Rs. 500 per boy for the first year and Rs 250 per boy for every subsequent year.

(b) The approved rate of expenditure on food is Rs. 4 per boy per day. The yearly expenditure on food per boy varies around Rs. 1100 to 1200. The clothing allowance is almost entirely spent for the purpose for which it is sanctioned. The remaining amount is utilised for the running expenses of the school, which include expenditure on the pay and allowances of the staff, text books, library, postage, telephones, other administrative necessities etc. Savings, if any, are credited to a reserve fund from which drawals are made as and when necessity arises. The amount spent on food and clothing meets the required standards.